"शिक्षा में पर्याप्त बजट आवंटन" पर डोर टू डोर अभियान

नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन के द्वारा शरद कालीन संसदीय बजट सत्र के दौरान दिल्ली में डोर टू डोर अभियान आयोजित किया गया। यह अभियान 2 से 4 जनवरी 2018 के बीच चलाया गया। अभियान का उद्देश्य शिक्षा में अपर्याप्त बजट आवंटन के मुद्दे पर सांसदों द्वारा संसद में सवाल उठाने के लिए तैयार करना था। एनसीई के प्रतिनिधियों ने वित्त पर बनी संसद की स्थायी समिति के सदस्यों के साथ मुलाक़ात कर उन्हें इस संबंध में मांग पत्र सौंपा। परिणामस्वरूप तीन सांसदों द्वारा संसद में इस मुद्दे पर सवाल उठाने की सहमति जताई गई।

'नो डिटेन्शन पॉलिसी' पर राष्ट्रीय बैठक

दिनांक 27 फरवरी 2018 को नो डिटेन्शन पॉलिसी पर एक दिवसीय राष्ट्र स्तरीय बैठक का आयोजन विश्व युवक केंद्र, नई दिल्ली में किया गया। उक्त बैठक का उद्देश्य सरकार द्वारा खत्म की जा रही 'नो डिटेन्शन पॉलिसी' को रोकने की रणनीति एवं सीसीई के क्रियान्वयन के निर्धारण में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा करना था। उक्त बैठक में NIEPA की प्रोफेसर श्रीमती नलिनी जुनेजा, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री प्रदीप चौधरी, CSEI के निदेशक श्री सत्येंद्र कुमार और केयर इंडिया की सुश्री सीमा राजपूत आदि प्रख्यात वक्ताओं ने इस विषय पर अपने विचारों को रखा। बैठक में निकले निष्कर्षों को लेकर एक कार्यवाही योजना तैयार की गई। कार्यवाही योजना के अंतर्गत 'नो डिटेन्शन पॉलिसी' को जारी रखने और सीसीई को बहाल रखने के लिए एनसीई द्वारा शिक्षक संगठनों के साथ मिलकर एक सामूहिक मांग पत्र तैयार किया गया जिसे सभी शिक्षक संगठनों ने अपने-अपने राज्यों में सांसदों को सौंपकर एनडीपी को न हटाने की मांग की। साथ ही एनसीई और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री प्रदीप चौधरी के संयुक्त प्रयास से "निजी विद्यालयों के लिए नियामक ढांचे" पर किए गए अध्ययन के सार (निष्कर्ष) को भी उक्त बैठक में प्रतिभागियों के समक्ष रखा गया। इस राष्ट्रीय बैठक में 15 राज्यों के शिक्षक संगठनों, शिक्षाविदों और नागर समाज संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा भागीदारी की गई।

एसडीजी 4 पर पुस्तिका एवं पोस्टर का विमोचन

एसडीजी-4 पर हर क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसपर 9 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित पुस्तिका का विमोचन 27 फरवरी को दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में किया गया। यह पुस्तिका हिन्दी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, तमिल, मराठी, असमिया, उड़िया और पंजाबी भाषाओं में अनुवादित की गई है। साथ ही एसडीजी 4 पर दो भाषाओं में तैयार एक पोस्टर का भी विमोचन इस राष्ट्रीय बैठक में किया गया।

'नो डिटेन्शन पॉलिसी' पर डोर टू डोर अभियान

मार्च 2018 के महीने में एनसीई द्वारा शिक्षक संगठनों के साथ मिलकर 12 राज्यों में 'नो डिटेन्शन पॉलिसी' पर डोर टू डोर अभियान चलाया गया। इस अभियान के माध्यम से सरकार द्वारा खत्म की जा रही नो डिटेन्शन पॉलिसी (जिसे संसद के मानसून बजट सत्र 2018 मे पेश किए जाने की संभावना थी) पर रोक लगाने और सीसीई के प्रभावी क्रियान्वयन पर संसद में सवाल उठाने के लिए माननीय सांसदों और विधायकों का समर्थन तैयार किया गया।

इस अभियान को असम, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, राजस्थान और महाराष्ट्र से प्रारम्भ किया गया। अभियान के दौरान राज्य स्तरीय प्राथमिक शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा माननीय सांसदों और विधायकों से उनके कार्यालयों और निवास स्थानों पर मुलाक़ात कर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा गया जिसमें नो डिटेन्शन पॉलिसी को खत्म करने पर रोक लगाने और सीसीई के प्रभावी क्रियान्वयन पर ज़ोर देने की बात की गई थी। इस मांग पत्र को हर राज्य से भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भी प्रेषित किया गया।

Social Media अभियान

अभियानों के क्रम में 'नो डिटेन्शन पॉलिसी' और 'फ़ंड फॉर पब्लिक एजुकेशन' पर हितभागियों के बीच व्यापक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से social Media (Facebook, Twitter और सामूहिक ईमेल) के माध्यम से दो अभियानों को संचालित किया गया। इन अभियानों के द्वारा हितभागियों (शिक्षक संगठनों एवं नागर समाज संगठनों) से यह अनुरोध किया गया कि 'नो डिटेन्शन पॉलिसी' को खत्म करने पर सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसले पर रोक लगाने और सीसीई के प्रभावी क्रियान्वयन पर आधारित मांग पत्र को वह सभी अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों को सौपें ताकि नो डिटेन्शन पॉलिसी को खत्म करने से रोका जा सके। साथ ही एसडीजी-4 के लक्ष्यों के बारे में हितभागियों को जानकारी देने के लिए हिन्दी और अँग्रेजी दो भाषाओं में तैयार पोस्टर को भी Social Media पर डाला गया।

ग्लोबल एक्शन वीक फॉर एजुकेशन

ग्लोबल कैम्पेन फॉर एजुकेशन (जीसीई) अपने सदस्य देशों के नेशनल कोएलीशन्स के साथ मिलकर शिक्षा के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने और सरकारों का इस पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से हर वर्ष ग्लोबल एक्शन वीक फॉर एजूकेशन के नाम से एक विश्वव्यापी अभियान चलाता है। भारत में नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन के साथ इस अभियान को संचालित किया जाता है। इस वर्ष 22 से 28 अप्रैल, 2018 के बीच जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के लिए वैश्विक कार्यवाही सप्ताह का आयोजन किया गया। एनसीई द्वारा वर्ल्ड विजन इंडिया के सहयोग से भारत के 20 राज्यों में इसे जिला एवं राज्य स्तर पर मनाया गया। इस अभियान का इस वर्ष का विषय "Vote for education: Citizen Action for Accountable Governments (शिक्षा के लिए वोट: सरकारों को उत्तरदायी बनाने के लिए नागरिक कार्रवाई)" था।

राज्य एवं जिला स्तर पर नुक्कड़ नाटकों, हस्ताक्षर अभियान, रैली, गोष्ठी, सम्मेलन एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन विभिन्न माध्यमों के द्वारा इस विषय पर आम नागरिकों से यह आह्वान किया गया कि 'एसडीजी 4' और 'शिक्षा 2030' के एजेंडा पर की गई प्रतिबद्धताओं पर सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को जिम्मेदार बनाने के लिए अपनी नागरिक सहभागिता बढ़ाएँ। शिक्षा के लिए वैश्विक कार्यवाही सप्ताह विभिन्न शिक्षक संगठनों, नागर समाज संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी संगठनों के साथ मिलकर मनाया गया।

इस साप्ताहिक अभियान का समापन समारोह 2 मई, 2018 को विश्व युवक केंद्र, दिल्ली मे आयोजित किया गया। इस समापन समारोह को एनसीई द्वारा यूनेस्को, सीबीएम इंडिया और वर्ल्ड विजन इंडिया के सहयोग से आयोजित किया गया। उक्त समारोह में प्रिया संस्था दिल्ली के डॉ राजेश टंडन, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की सुश्री किरण भाटी, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर पूनम बत्रा, CBGA के श्री अब्दुल्ला, RTE फोरम के श्री अम्बरीश राय, YP Foundation की सुश्री श्रुति अरोड़ा, CSEI के श्री करणदीप भगत, CBM India के श्री कुमार रतन एवं श्री सत्यम श्रीवास्तव आदि गणमान्य व्यक्ति मुख्य वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उक्त कार्यक्रम में भारत के 20 राज्यों के शिक्षक संगठनों, नागर समाज संगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी कर स्थानीय स्तर पर आयोजित इस अभियान से जुड़े अनुभवों को साझा किया। साथ ही इस मुद्दे पर तैयार किए गए मांग पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत के प्रधानमंत्री को भेजा गया।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति को महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में परिभाषित किया गया है। समिति के माध्यम से अभिभावकों की भागीदारी से ही विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को कैसे बढ़ावा मिलेगा? इस विषय पर विद्यालय प्रबंधन समिति की समझ विकसित करने के लिए राष्ट्र स्तर पर प्रशिक्षकों की एक टीम तैयार की गई जिन्होंने स्थानीय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति को इस विषय पर प्रशिक्षित किया।

प्रशिक्षकों के इस टीम का एक दिवसीय प्रशिक्षण 3 मई, 2018 को एनसीई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नागर समाज संगठनों के 12 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभागिता की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 'विद्यालय के संदर्भ में समावेशी शिक्षा' के विषय पर प्रतिभागियों की समझ बनाने का प्रयास किया गया। इस विषय में विद्यालय प्रबंधन समितियों की भूमिका और जिम्मेदारियां तथा विद्यालय विकास योजना पर प्रशिक्षकों द्वारा कई सत्र लिए गए।

'समावेशी शिक्षा' पर विद्यालय प्रबंधन समितियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

समावेशी शिक्षा पर समझ बढ़ाने और इस विषय को लेकर विद्यालय विकास योजना विकसित करने के उद्देश्य को लेकर भारत के तीन राज्यों में विद्यालय प्रबंधन समितियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन तीन राज्यों में कुल 23 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा संचालित किए गए। इन कार्यक्रमों में 230 विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समितियों के 714 सदस्यों ने प्रतिभाग किया गया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 मई से 3 जुलाई तक बिहार के भोजपुर और बक्सर जिले में मदद संस्था के सहयोग से, आंध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में सीड्स संस्था के सहयोग से और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एन ब्लॉक-ऑन वे टू हयूमैनिटी के सहयोग से संचालित किए गए।

क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला

एनसीई द्वारा दिनांक 6 अप्रैल, 2018 को बंगलौर में एक क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 'मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में (निजी विद्यालयों के लिए नियामक ढांचे)' विषय पर विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला को कर्नाटक राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 'नो डिटेन्शन पॉलिसी' को खत्म करने के विरोध में नागर समाज संगठनों और शिक्षक संगठनों को एक मंच पर लाना था। यह परामर्श कार्यशाला 12 दिसंबर, 2017 को 'मानव अधिकार एवं शिक्षा' पर दिल्ली में आयोजित की गई कार्यशाला की निरंतरता में की गई थी। इसमें 12 राज्यों के 86 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें AIPTF, AIFTO, AISTF आदि शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ WORLD VISION INDIA, CBMONDEDE, HRF आदि स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि एवं शिक्षाविद् भी शामिल थे। इसमें एनसीई बोर्ड के सदस्यों द्वारा भी भागीदारी की गई।

'मानव अधिकार शिक्षा और समावेशी शिक्षा' पर क्षमतावृद्धि कार्यशाला

एनसीई ने Amnesty International के साथ मिलकर 'मानव अधिकार शिक्षा और समावेशी शिक्षा' पर समझ बनाने के लिए तीन दिवसीय क्षमतावृद्धि कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला महाराष्ट्र के मुंबई शहर में 8 से 10 जून को आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य नागर समाज और शिक्षक संगठनों की मानव अधिकार शिक्षा पर समझ विकसित करना साथ ही उन्हें लिंग (जेंडर) अवधारणा विषय पर संवेदनशील भी बनाना था जिससे वे अपने कार्य में इन मुद्दों को शामिल कर विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करा सकें। कार्यशाला में 15 राज्यों के 35 प्रतिभागियों ने भागीदारी की जिसमें एनसीई स्टाफ, एनसीई की सहयोगी संस्थाओं तथा शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस कार्यशाला के फॉलोअप में उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली के लगभग 15 विद्यालयों में मानव अधिकार क्लब बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

भारत में निजी विद्यालयों के लिए नियामक ढांचे और पारदर्शिता तंत्र पर एक शोध

शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नियमन के संदर्भ में निजी स्कूल संचालन के लिए मानदंडों और नियामक तंत्र पर एनसीई द्वारा एक अध्ययन किया गया। यह अध्ययन आंध्र प्रदेश और दिल्ली में किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य निजी स्कूलों द्वारा लगाए गए शुल्क और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को नियंत्रित करने वाले सरकारी तंत्र की जांच करना था। इस अध्ययन में ऐसे बहुत ही कम मामले पाए गए जिसमें सरकार ने स्थापित शुल्क विनियमन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ निजी स्कूलों पर कार्रवाई की है।

एनसीई कोना

बधाई

"स्कूल एक बच्चे के विकास के लिए सबसे अच्छा परिसर है। शिक्षकों को स्कूल में रुचिकर गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे उनके सीखने की गति बढ़ जाती है।" ऐसा कहना है आशा जी का, जोकि दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए आशा जी को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। 2008-09 में उन्हें दिल्ली के नजफगढ़ ब्लॉक के 89 स्कूलों के शिक्षकों में से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में चुना गया था। उन्हें इसके लिए नजफगढ़ नगर निगम द्वारा सम्मानित किया गया था। इसके बाद, 2013-14 में उन्हें दुबारा दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा जिले में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया।

सुश्री आशा जी के साथ किए गए एक साक्षात्कार में उन्होने साझा किया गया कि वे स्वयं अनुसूचित जाति समुदाय से आती हैं, इसलिए वे वंचित और शोषित वर्ग से आने वाले बच्चों की अच्छी देखभाल करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन बच्चों को विशेष सहायता की आवश्यकता है। उनका मानना है कि 'केवल शिक्षा ही जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर समाज में मौजूदा भेदभाव को रोक सकती है।' दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले शिक्षकों को हर वर्ष सम्मानित किया जाता है, इसी कड़ी में सुश्री आशा जी को वर्ष 2018 में भी शिक्षा विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया।

एनसीई परिवार की ओर से उन्हें बहुत-बहुत बधाई!

NATIONAL COALITION FOR EDUCATION

'Shikshak Bhawan', 41-Institutional Area, D-Block, Janakpuri, New Delhi-110058

Ph.: + 91 11 28526851 | **Website:** www.nceindia.org | **Email:** info@nceindia.org

Facebook: facebook.com/nceindia | **Twitter:** twitter.com/nceindia | **Blog:** ncedelhi.blogspot.com

All India Federation of Teachers Organisatio | AISTF All India Secondary Teachers' Federation | PCCSS Peoples Campaign for Common | World Vision

DRV # 9811111621